

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5520
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी

5520. श्री राहुल कस्वां :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कीमतों को स्थिर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) वैश्विक स्तर पर विभिन्न तेल उत्पादक कंपनियों (ओपीसी) पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल सहित पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए क्या नए उपाय किए गए हैं; और
- (ग) क्या देश में पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल और घरेलू एलपीजी की कीमतों में वृद्धि और कमी के संबंध में कोई उच्च स्तरीय समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)**

(क) से (ग): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लेती हैं।

भारत सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजारों के साथ-साथ भूराजनैतिक परिस्थितियों से उत्पन्न संघर्ष के चलते संभाव्य ऊर्जा आपूर्ति में बाधा की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है। कच्चे तेल की आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी एकल क्षेत्र से कच्चे तेल के लिए निर्भरता का जोखिम कम करने के निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) ने अपने पेट्रोलियम आयात बास्केट को विविधीकृत किया है और विभिन्न भौगोलिक स्थलों पर अवस्थित देशों से कच्चे तेल की अधिप्राप्ति कर रहे हैं।

सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल थे।

घरेलू स्तर पर, सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्य कम हो कर क्रमशः 94.77 रुपए और 87.67 रुपए प्रति लीटर (दिल्ली के मूल्य) हो गए हैं, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2021 और मई 2022 में दो बार पेट्रोल और डीजल पर कुल मिलाकर क्रमशः 13 रुपए प्रति लीटर और 16 रुपए प्रति लीटर की केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की गई, जिसका लाभ पूरी तरह से

उपभोक्ताओं को दे दिया गया। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरों में कमी की। मार्च 2024 में, ओएमसीज ने पेट्रोल और डीजल प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की।

पीएसयू ओएमसीज ने हाल ही में अंतर्राज्यीय माल भाड़े को युक्तिसंगत बनाया है। इससे राज्यों के दूरदराज के हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम तेल और ल्यूब्रिकेंटों (पीओएल) डिपो से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इस पहल ने एक राज्य के भीतर पेट्रोल या डीजल की अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच के अन्तर को भी कम कर दिया है।

भारत दुनिया की एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था रही है जहां हाल के वर्षों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी आयी है। नवंबर, 2021 और जनवरी, 2025 के मध्य कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में परिवर्तन निम्नानुसार है:

	नवंबर-21 और जनवरी-25 के बीच मूल्यों में परिवर्तन का %	
देश	पेट्रोल	डीज़ल
भारत (दिल्ली)	-13.60%	-10.92%
फ्रांस	14.21 %	15.08 %
जर्मनी	7.87 %	12.43 %
इटली	8.65 %	11.39 %
स्पेन	8.67 %	12.93 %
यूके	0.08 %	2.61 %
कनाडा	10.52 %	23.05 %
यूएसए	4.83 %	12.86 %

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

नवंबर, 2021 और जनवरी, 2025 के बीच कुछ पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में परिवर्तन -

	नवंबर-21 और जनवरी-25 के बीच मूल्यों में परिवर्तन का %	
देश	पेट्रोल	डीज़ल
भारत (दिल्ली)	-13.60%	-10.92%
पाकिस्तान	29.76 %	34.97 %
बांग्लादेश	13.94 %	30.82 %
श्रीलंका	53.98 %	101.59 %
नेपाल	22.02 %	31.32 %

स्रोत(पीपीएसी) षण प्रकोष्ठपेट्रोलियम योजना एवं विश्ले :

भारत घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़ा हुआ है। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 63% की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में 385 यूएस डॉलर/मीट्रिक टन से फरवरी 2025 में 629 यूएस डॉलर/मीट्रिक टन), घरेलू एलपीजी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य में 44% तक (अगस्त 2023 में 903 रुपए से फरवरी 2025 में 503 रुपए) की कमी की गई।

सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और किफायती बनाने के लिए तथा उनके द्वारा एलपीजी के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम

के कनेक्शनों के लिए अनुपातिक रूप से समानुपाती) 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता शुरू की थी। सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी के मूल्यों को अगस्त, 2023 में 200 रुपए तथा मार्च, 2024 में 100 रुपए कम किया गया था। सरकार ने अक्टूबर, 2023 से निर्धारित राजसहायता को प्रतिवर्ष 12 रिफिलों तक (तथा 5 किलोग्राम के कनेक्शनों के लिए अनुपातिक रूप से समानुपाती) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर को बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया था। सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी 803 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर (दिल्ली मूल्य) पर प्राप्त हो रही है। वर्तमान में राजसहायता धनराशि बढ़ाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वैश्विक स्तर पर, पीएमयूवाई अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 10.33 करोड़ से भी अधिक गरीब परिवारों को लगभग 35 रुपए/किलोग्राम के प्रभावी मूल्य पर घरेलू एलपीजी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, पड़ोसी देशों में दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलिंडर का प्रभावी मूल्य निम्नानुसार है-

देश	घरेलू एलपीजी (रुपए/14.2 किलोग्राम सिलिंडर)
भारत	503.00*
पाकिस्तान	1094.83
श्रीलंका	1231.53
नेपाल	1206.65

स्रोत- पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

*दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत, गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य 803 रुपए है।
